



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 2000/ज्येष्ठ 3, 1922

No. 61]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24, 2000/JYAISTHA 3, 1922

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2000

सं. टीएएमपी/5/2000-सीओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार कोचीन पत्तन में आने वाले विदेशी पर्यटन यात्रा वाले जहाजों को पोत-संबद्ध प्रभारों के 33 $\frac{1}{3}$ प्रतिशत की छूट प्रदान करने के कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/5/2000-सीओपीटी

कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी)

आवेदक

आदेश

(मई, 2000 के 12वें दिन को पारित किया गया)

कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) ने कोचीन पत्तन में आने वाले विदेशी पर्यटन यात्रा वाले जहाजों को पोत-संबद्ध प्रभारों के 33 $\frac{1}{3}$ प्रतिशत की छूट प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

2. सीओपीटी के बोर्ड ने इस प्राधिकरण के अनुमोदन के शर्ताधीन इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। सीओपीटी के बोर्ड द्वारा विचार किए गए विषयगत प्रस्ताव की कार्यसूची टिप्पणी में इस प्रस्ताव के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं :-

“कोचीन पत्तन में आने वाले यात्री जहाजों को कुछ रियायतें देने के लिए यात्री जहाजों के एजेंटों से अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान कोचीन पत्तन में प्रत्येक वर्ष 21 यात्री जहाज आए हैं। केरल सरकार के पर्यटन और अनिवासी केरलवासी मामलों के विभाग ने भी यात्री जहाजों को पोत-संबद्ध प्रभारों पर कुछ छूट प्रदान करने के लिए अनुरोध किया था। दुबई को पर्यटकों के लिए एक बड़े पर्यटक-स्थल के रूप में विकसित किया गया है। इसलिए, कुछ नीतिगत उपाय आरंभ करना आवश्यक समझा गया ताकि कोचीन को एक आकर्षक पर्यटक स्थल बनाया जा

सके । कोचीन पत्तन में लगाया जाने वाला 0.78 अमरीकी डालर प्रति जीआरटी का प्रभार चेन्नई, मुंबई और मोरमुगांव जैसे अन्य पत्तनों की तुलना में बहुत अधिक है । यह कोचीन पत्तन में आने वाले विदेशी पर्यटन यात्रा वाले जहाजों को हतोत्साहित करता है । तथापि, तटीय यात्री जहाज रियायती प्रशुल्क का पहले ही लाभ उठा रहे हैं, जोकि 11.30 रुपए प्रति जीआरटी बैठता है ।”

3. हमारे द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार, यह प्रस्ताव कोचीन स्टीमर एजेंट्स संघ (सीएसए) और कोचीन वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (सीसीसीआई) को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था ।

4. सीएसए ने प्रस्ताव का स्वागत किया है और यह मत व्यक्त किया कि प्रस्तावित कार्रवाई से कोचीन पत्तन में अधिकाधिक यात्री जहाज आएंगे । उनकी विभिन्न यात्री पोतस्वामियों और ऑपरेटरों के साथ हुई बातचीत से पता चला है कि प्रस्तावित कमी से पोत स्वामियों को उनकी पर्यटन पोत यात्रा में कोचीन पत्तन को भी शामिल करने के लिए मनाया जा सकेगा । सभी ऑपरेटर यह अनुभव करते हैं कि अत्यधिक पत्तन लागत पोतस्वामियों को यात्रियों से उच्च प्रशुल्क वसूल करने के लिए मजबूर करती है, जिससे कोचीन पत्तन में से अधिक यात्री यातायात को गुजरने में बाधा आती है ।

5. इस मामले में सीओपीटी में एक सुनवाई आयोजित की गई थी । संयुक्त सुनवाई में सीओपीटी और सीएसए ने भाग लिया था । सीओपीटी ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं :—

- (i) पर्यटक जहाजों के लिए सीओपीटी के प्रभार इस क्षेत्र में सबसे ऊंचे हैं ।
- (ii) रियायत दिए जाने पर सीओपीटी में इस प्रकार के और अधिक जहाज आएंगे ।

6. सीएसए ने उल्लेख किया है कि ये रियायतें न केवल यात्री यातायात प्राप्त करने के लिए बल्कि वर्तमान स्तर को भी बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं । उन्हें डर है कि सीओपीटी द्वारा इस समय वसूल किए जा रहे उच्च प्रशुल्क के कारण समुद्री पर्यटक ऑपरेटरों की नाराजगी की वजह से यातायात कम हो सकता है ।

7. यह देखते हुए कि छांचागत सुविधाओं में किसी सुधार के बिना रियायती प्रशुल्क की अनुमति देने पर संभवतः आशा के अनुरूप विदेशी समुद्र पर्यटक जहाज न आएँ, इसलिए इस प्राधिकरण ने सीओपीटी से निम्नलिखित स्पष्टीकरण मांगे थे :—

- (i) पत्तन सुविधाओं और अन्य सुख-सुविधाओं में सुधार के लिए प्रस्ताव ।
- (ii) ऐसी सुविधाएं प्रदान करने वाली एजेंसी ।
- (iii) वह समय अवधि, जिसके लिए (प्रस्तावित) रियायत जारी रहने की संभावना है ।

8. सीओपीटी ने अपने उत्तर में निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं :—

- (i) यदि कोई समुद्री पर्यटक जहाज त्रिवेन्द्रम में लंगर डालता है और यात्रियों को छोटे जहाजों द्वारा तट पर ले जाया जाता है, तब 17,490 जीआरटी के समुद्री पर्यटक जहाज के लिए देय प्रभार केवल 4,651 अमरीकी डॉलर है, जबकि सीओपीटी में देय प्रभार 16,144 अमरीकी डॉलर है । वर्तमान पत्तन प्रभार के जारी रहने से कुछ ऑपरेटर केरल में ऐसे लंगरगाह पत्तनों का

प्रयोग करने के लिए मजबूर हो सकते हैं और सीओपीटी समुद्री पर्यटक जहाजों की सेवा करने का अवसर खो बैठेगा ।

- (ii) सीओपीटी ने केरल सरकार को सूचित किया है कि कोचीन में आने वाले यात्री जहाजों की संख्या बहुत कम है और यात्री जहाजों के माध्यम से होने वाली पत्तन की आय एक संपूर्ण यात्री टर्मिनल चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है । सीओपीटी अब बोट ट्रेन पायर का पुनर्निर्माण कर रहा है, जिसे आवश्यक सुविधाओं और यात्री जहाजों को प्रहस्तन करने के लिए आधारभूत ढांचे के साथ एक सामान्य कार्गो बर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा । इस पत्तन में आने वाले विश्व स्तरीय ऐश्वर्यपूर्ण समुद्री पर्यटक जहाजों को नौतल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और यात्रीगण स्थानीय दर्शनीय स्थलों में रुचि लेंगे । आच्छादित शैल्टर जैसी सुविधाएं यदि उपलब्ध कराई जाती हैं, यात्रियों द्वारा उनका प्रयोग किए जाने की संभावना नहीं है । आधारभूत सुविधाओं की कमी मुख्य बाधा नहीं है, क्योंकि कोचीन कोई प्रमुख/प्रारंभिक यात्री चढ़ने वाला पत्तन नहीं है, बल्कि केवल एक पारगमन पत्तन है ।
- (iii) सीओपीटी के अनुरोध पर केरल सरकार यात्री जहाजों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यय में हिस्सेदारी करने के लिए आगे आई है । सुविधाएं पत्तन न्यास द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी । इसके लिए दीर्घावधि योजना की आवश्यकता होगी और हिस्सेदारी के तौर-तरीकों के बारे में केरल सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चाएं करनी होंगी ।
- (iv) विदेशी समुद्री पर्यटक जहाजों को पोत-संबद्ध प्रभारों पर $33 \frac{1}{3}$ प्रतिशत की छूट अगले आम संशोधन में दरें संशोधित किए जाने तक जारी रखनी होंगी और विदेशी समुद्री पर्यटक जहाजों के लिए एक अलग दर की व्यवस्था करनी होगी ।

9. इस मामले की जांच-पड़ताल के दौरान एकत्रित समग्र सूचना के संदर्भ में और समग्र ध्यान दिए जाने के आधार पर निम्नलिखित स्थिति उभरती दिखाई देती है :—

- (i) इस प्राधिकरण की पूछताछ के प्रत्युत्तर में सीओपीटी द्वारा दिए गए उत्तर तर्कसंगत पाए गए हैं और इसलिए स्वीकार्य हैं ।
- (ii) सीओपीटी ने यह मामला केरल सरकार के साथ उठाया है, जोकि यात्री जहाजों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यय में हिस्सेदारी करने के लिए सहमत हो गए हैं ।
- (iii) सीओपीटी ने अनुमान लगाया है कि प्रस्तावित कमी के कारण होने वाले राजस्व की हानि की यातायात में होने वाली परिणामी वृद्धि से भरपाई हो जाएगी । इस अनुमान की जांच करने का इस प्राधिकरण के पास कोई आधार नहीं है । लेकिन, सीएसएए के भारी समर्थन के कारण इस पर ध्यान न देने की भी कोई वजह दिखाई नहीं देती ।
- (iv) वस्तुतः, हमारे पत्तनों में समुद्री पर्यटक जहाजों का यातायात नाममात्र है । यदि इसमें बढ़ोतरी होती है, तभी यह लाभदायक है । इससे पत्तनों को अनेक अनुवर्ती लाभ हो सकते हैं ।

10. परिणामतः और ऊपर दिए गए कारणों को देखते हुए यह प्राधिकरण कोचीन पत्तन न्यास में आने वाले विदेशी समुद्री पर्यटक जहाजों को पोत-संबद्ध प्रभारों के $33 \frac{1}{3}$ प्रतिशत की छूट प्रदान करने के लिए सीओपीटी के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है ।

11. सीओपीटी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने दरों के मान में प्राधिकरण के इस निर्णय को शामिल करें ।
12. उपर्युक्त छूट इस आदेश के अधिसूचित किए जाने की तारीख से 30 दिन समाप्त होने के पश्चात प्रभावी हो जाएगी ।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/3/4/असाधारण/143/2000]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th May, 2000

No. TAMP/5/2000-COPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal of the Cochin Port Trust (COPT) to grant a rebate of $33\frac{1}{3}\%$ of vessel-related charges to foreign cruise vessels calling at the Cochin Port, as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

Case No. TAMP/5/2000-COPT

The Cochin Port Trust

...

Applicant

ORDER

(Passed on this 12th day of May 2000.)

The Cochin Port Trust (COPT) has submitted a proposal to grant a rebate of $33\frac{1}{3}\%$ of vessel-related charges to foreign cruise vessels calling at the Cochin Port.

2. The Board of the COPT endorsed this proposal, subject to the approval of this Authority. The agenda note on the subject proposal considered by the Board of the COPT contains the following arguments in support of the proposal:

"There have been requests from agents of passenger vessels for giving certain concessions to passenger vessels calling at Cochin Port. During 1997-98 and 1998-99, 21 passenger ships each year have called at Cochin Port. The Tourism and Department for Non-Resident Keralites' Affairs of Government of Kerala had also requested to grant some rebate on vessel-related charges to passenger vessels. Dubai has been developed as a huge tourist destination for tourists. It is therefore considered necessary to initiate policy measures which can make Cochin as a tourist destination attractive. The charges amounting to US \$ 0.78 per GRT levied at Cochin Port are much higher, when compared to other ports like Chennai, Mumbai, and Mormugao. This is a

disincentive to foreign cruise vessels calling at Cochin Port. However, coastal passenger vessels have already been enjoying concessional tariff which works out to be Rs.11.30 per GRT."

3. In accordance with the procedure adopted by us, the proposal was circulated to the Cochin Steamer Agents' Association (CSAA) and the Cochin Chamber of Commerce and Industry (CCCI), seeking their comments.

4. The CSAA has welcomed the proposal and opined that the proposed move will bring more and more passenger vessels to the Cochin Port. Their consultation with various passenger vessel owners and operators is reported to have revealed that the proposed reduction will persuade owners to include the Cochin Port in their cruise vessels' itinerary. All operators feel that the very high port cost compel the owners to collect high tariffs from the passengers which stands in the way of more passenger traffic going through the Cochin Port.

5. A joint hearing in this case was held at the COPT. The COPT and the CSAA participated in the joint hearing. The COPT has made the following points:

- (i). COPT charges for cruise vessels are the highest in the region.
- (ii). COPT will get more such vessels calling by giving concession.

6. The CSAA has stated that concessions are required not only to gain passenger traffic but also to maintain it at the present level. They fear that the traffic might wane, due to the annoyance of cruise operators over the existing high tariff levied by the COPT.

7. Observing that allowing concessional tariff without any improvement in the infrastructure facility may perhaps not attract foreign cruise vessels, as anticipated, this Authority sought following clarifications from the COPT:

- (i). The proposal for improvement of port facilities and other amenities.
- (ii). The agency which is going to provide such facilities.
- (iii). The time period for which the (proposed) concession is likely to continue.

8. In reply, the COPT has furnished following comments:

- (i). If a cruise vessel is anchored at Trivandrum and the passengers are taken ashore by smaller vessels, the charges payable for a cruise vessel of GRT 17,490 is US \$ 4,651 only whereas the charges payable at COPT is US \$ 16,144. The continuation of the present Port Charges may compel some of the operators to use such anchorage Ports in Kerala and the COPT will lose the opportunity of serving cruise vessels.

- (ii). The COPT has intimated the Government of Kerala that the number of passenger vessels calling at Cochin are few and Port's income by way of passenger vessels is not adequate to support a full fledged passenger terminal. The COPT is now reconstructing the Boat Train Pier which will be developed into a general cargo berth with necessary facilities and infrastructure to handle passenger vessels also. The world-class luxury cruise vessels calling at this port will have all the facilities on board and the passengers are mostly interested in local sight seeing. Facilities like covered shelter, etc., if provided, are not likely to be used by the passengers. The lack of basic facilities is not a major constraint since Cochin is not a major/primary passenger boarding Port but only a transit Port.
- (iii). On COPT's request, the Government of Kerala has come forward to share the expenditure on providing facilities for passenger vessels. The facilities are to be provided by the port trust. This will require long term planning and the modalities of sharing, etc., have to be discussed with the representatives of Government of Kerala.
- (iv). The rebate of $33\frac{1}{3}\%$ on vessel related charges to foreign cruise vessels will have to continue till the rates are revised in the next general revision and a separate rate is provided for foreign cruise vessels.

9. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, and based on a collective application of mind, the following position is seen to emerge:

- (i). The replies given by the COPT in response to the queries of this Authority are found to be reasonable and hence acceptable.
- (ii). The COPT has taken up the issue with the Government of Kerala, which has agreed to share the expenditure on providing facilities to passenger vessels.
- (iii). The COPT has estimated that the loss of revenue by the proposed reduction will be more than made up by the consequential increase in traffic. There is no basis for this Authority to verify this estimate. But, going by the enthusiastic support of the CSAA, there does not appear to be any reason to discount it either.
- (iv). Admittedly, cruise-vessel traffic in our ports is negligible. If it can increase, it can only be beneficial. There may be many spin-off benefits to the ports.

10. In the result, and for the reasons given above, the Authority approves the proposal of the COPT to grant a rebate of $33\frac{1}{3}\%$ of vessel related charges to foreign cruises vessel calling at the Cochin Port Trust.

11. The COPT is directed to incorporate this decision of the Authority in its Scale of Rates.

12. The above rebate shall come into force on expiry of 30 days from the date of the Notification of this Order.

S. SATHYAM, Chairman
[Advt./III/IV/Exty./143/2000]

